Drishti IAS

# करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

## दिसंबर 2022

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

# अनुक्रम


**उत्तर प्रदेश** **3**

- उत्तर प्रदेश पुरातत्त्व निदेशालय की 'एडाप्ट ए हेरिटेज योजना' के दूसरे चरण में दस धरोहरों का चयन 3
- गीडा को मिला जीआईएस 2023 में 40 हज़ार करोड़ के निवेश का लक्ष्य 3
- रेड टेप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले पद्मश्री इरशाद मिर्ज़ा का निधन 4
- उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया 33 हज़ार 700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट 4
- गंगा बेसिन में लागू होगा गंगा मित्रों का मॉडल 5
- उत्तर प्रदेश में बनेंगे एकीकृत न्यायालय परिसर 6
- उत्तर प्रदेश के 6 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के टेंडर जारी 7
- ओडीओपी की तर्ज पर 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन वेटलैंड' की तैयारी 7
- 'पहचान' से एक क्लिक पर खुलेगी माध्यमिक स्कूलों की कुंडली 8
- प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया 8
- यमुनापार क्षेत्र में 624 करोड़ की योजना स्वीकृत 9
- उत्तर प्रदेश रोज़गार देने में देश में अव्वल 9
- उत्तर प्रदेश में 5 हज़ार एकड़ में बनेगी नॉलेज स्मार्ट सिटी 10
- उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भी खुलेंगे जेनेरिक आधार के स्टोर 10
- आईएचआरसी का 63वाँ सत्र उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार में आयोजित 11
- वाराणसी में बनेगा ओडीओपी मॉल 11
- सामाजिक प्रगति करने में 31वें स्थान पर उत्तर प्रदेश 12
- रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के लिये लखनऊ में आधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंज़ूरी दी 13
- सीसीआरएएस-सीएआरआई, झाँसी को एनएबीएल की मान्यता 13
- देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी मिर्ज़ापुर की सानिया मिर्ज़ा 14
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में यातायात विस्तार 14
- 336 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा काशी इंटर मॉडल स्टेशन 15
- उत्तर प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में एचएमआईएस सेवा प्रारंभ 15
- अब चौरीचौरा नाम से जाना जाएगा गोरखपुर का मुंडेरा बाज़ार नगर पंचायत 16
- पहली बार ईको टूरिज़्म थीम पर आयोजित होगा गोरखपुर महोत्सव 16
- टाइगर के बाद अब लेपर्ड कैट का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा दुधवा 17
- साबरमती की तर्ज पर अयोध्या में बसेगी ग्रीनफील्ड टाउनशिप 17
- हिन्दी संस्थान के 46वें स्थापना दिवस पर 70 साहित्यकार सम्मानित 18
- GIS 2023: यूपीसीडा ने हासिल किये एक लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 83 हज़ार करोड़ रुपए के एमओयू साइन 18


**नोट :**

# उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश पुरातत्त्व निदेशालय की 'एडाप्ट ए हेरिटेज योजना' के दूसरे चरण में दस धरोहरों का चयन

### चर्चा में क्यों ?

30 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश पुरातत्त्व निदेशालय की निदेशक रेनू द्विवेदी ने बताया कि राज्य में 'एडाप्ट ए हेरिटेज योजना'के दूसरे चरण में 10 धरोहरों का चयन किया गया है।

### प्रमुख बिंदु

- रेनू द्विवेदी ने बताया कि 'एडाप्ट ए हेरिटेज योजना'के दूसरे चरण में लखनऊ के आलमबाग भवन समेत पोतराकुंड (मथुरा), कल्पा देवी एवं आस्तिक बाबा मंदिर (सीतापुर), देवगढ़ की बौद्ध गुफाएँ (ललितपुर), राज मंदिर गुप्तार घाट (अयोध्या), लक्ष्मी मंदिर (झाँसी), टहरौली किला (झाँसी), बालाबेहट किला (ललितपुर), दिगारा गढ़ी (झाँसी) तथा शिव मंदिर (टिकैतराय बिठूर कानपुर) को शामिल किया गया है।
- उन्होंने बताया कि स्मारक मित्र के साथ पाँच साल का मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) साइन किया जाएगा, जिसके तहत गोद लिये गए धरोहर पर काम कराना होगा। धरोहर को सहेजने के साथ ही वहाँ पर अस्थायी निर्माण व अन्य माध्यमों से स्मारक मित्र आमदनी भी कर सकेंगे।
- राज्य सहायक पुरातत्त्व अधिकारी डॉ. राजीव त्रिवेदी ने बताया कि स्मारक मित्र द्वारा स्मारकों पर कराए जाने वाले काम तय किये गए हैं। स्थल पर संकेतक, पेयजल, बिजली, सीवरेज, जन सुविधाएँ, वाई-फाई, बेंच, कूड़ादान, प्रकाश, पहुँच मार्ग एवं पाथवे, कैफेटेरिया, दिव्यांग के लिये रैंप एवं व्हीलचेयर की व्यवस्था आदि काम कराने होंगे।
- गोद लिये गए धरोहर पर स्मारक मित्रों द्वारा कराए जाने वाले कामों की निगरानी के लिये स्मारक समिति भी गठित की गई है, जो समय-समय पर निरीक्षण करेगी।
- स्मारक मित्र गोद लिये गए धरोहर पर अनुरक्षण एवं परिरक्षण नहीं कर सकेंगे। यह काम पुरातात्त्विक मानकों के अनुरूप विभाग द्वारा ही कराया जाएगा। स्मारक मित्र अस्थायी निर्माण तो करा सकेंगे पर स्मारक पर किसी तरह का कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगा सकते।
- रेनू द्विवेदी ने बताया कि राज्य पुरातत्त्व निदेशालय, पर्यटन विभाग और अन्य स्टेकहोल्डरों के सहयोग से स्मारकों एवं पुरास्थलों पर उच्च स्तरीय पर्यटन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये धरोहरों को गोद लेने की योजना शुरू की गई थी। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 11 स्मारकों एवं पुरास्थलों को गोद लेने के लिये चुना गया था।

## गीडा को मिला जीआईएस 2023 में 40 हज़ार करोड़ के निवेश का लक्ष्य

### चर्चा में क्यों ?

1 दिसंबर, 2022 को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के सीईओ पवन अग्रवाल ने बताया कि गीडा को फरवरी 2023 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) में 40 हज़ार करोड़ का निवेश कराने का लक्ष्य मिला है।

### प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 30 नवंबर को गीडा के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोज़गार सृजन करने वाले करोड़ों रुपए के निवेश व विकास परियोजनाओं की सौगात देकर उद्यमियों में विकास की डोर को और मज़बूत किया है।
- गीडा दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने 504 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं को गति देने के साथ ही 1200 करोड़ रुपए के भावी निवेश की परियोजनाओं के लिये 2.42 लाख वर्गमीटर से अधिक भूमि के आवंटनपत्र भी वितरित किये।

नोट :

- इन परियोजनाओं में वैश्विक स्तर की प्रतिष्ठित कंपनी पेप्सिको की फ्रेंचाइजी मेसर्स वरुण बेवरेजेस की तरफ से 1071 करोड़ रुपए तथा सेंट्रल वेयरहाउसिंग की तरफ से 40 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हैं।
- गीडा में बहुउद्देश्यीय प्लास्टिक पार्क और रेडीमेड गारमेंट की फ्लैटेड फैक्ट्री का शिलान्यास कर मुख्यमंत्री ने करीब 172 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का मार्ग खोला है। करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे प्लास्टिक पार्क में 92 तथा करीब 34 करोड़ रुपए की लागत वाली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 80 इकाइयाँ लग सकेंगी।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर देश-दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने के साथ ही सरकार का ध्यान प्रदेश के निवेशकों को भी उत्साहित करने पर है। खुद मुख्यमंत्री लगातार गोरखपुर समेत पूर्वांचल के स्थानीय उद्यमियों से यह आह्वान कर रहे हैं कि वे जीआईएस-2023 में भागीदारी करते हुए और अधिक निवेश को आगे आएँ।
- निवेश और इसके ज़रिये बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि ज़िले स्तर पर प्रतिमाह और मंडल स्तर पर हर तीन माह में बैठक कर उद्यमियों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसी क्रम में गीडा को भी उद्यमियों से जीआईएस 2023 में ज्यादा से ज्यादा निवेश का लक्ष्य मिला है।

## रेड टेप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले पद्मश्री इरशाद मिर्जा का निधन

### चर्चा में क्यों ?

4 दिसंबर, 2022 को रेड टेप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले, चर्म निर्यातक और मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन पद्मश्री इरशाद मिर्जा का बीमारी के चलते निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे।

### प्रमुख बिंदु

- इरशाद मिर्जा ने कंपनी की शुरुआत की 1979 में की थी, जो लेदर बनाने और टैनिंग व फिनिशिंग के लिये काम करती है। कंपनी में बनने वाला लेदर विदेश में भी एक्सपोर्ट होता है। उनका नाम फोर्ब्स मैगजीन की प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में आ चुका है।
- इरशाद मिर्जा ने अपने कॅरियर की शुरुआत वर्ष 1973 में चमड़े के सामान (काठी उत्पाद) के एक निर्यातक के तौर पर की। 32 वर्षों की अवधि में उन्होंने एक निर्यात व्यवसाय खड़ा किया, जिसका कारोबार लगभग 350 करोड़ रुपए है। इसमें 11000 लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार से जुड़े हैं। वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समकालीन काठी (सैडलरी) विकसित की और इसे ऑस्ट्रेलिया ले गए, जहाँ इसे खूब पसंद किया गया।
- गौरतलब है कि इरशाद मिर्जा राजनाथ सिंह की उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
- इरशाद मिर्जा ने एक शैक्षणिक संस्थान, एक साहित्य प्रचार अकादमी और कई अन्य संस्थानों की स्थापना की है। वह रोटरी क्लब के कानपुर चैप्टर के अध्यक्ष भी रहे हैं।
- मिर्जा फाउंडेशन से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों और ग्रामीणों को उच्च श्रेणी की चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के लिये अपने कारखानों के पास 100 बिस्तरों वाला अस्पताल भी बनवाया है।
- वह चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के प्रबंध समिति के सदस्य तथा उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के निदेशक की जिम्मेदारियाँ सँभाल चुके हैं।

## उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया 33 हज़ार 700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट

### चर्चा में क्यों ?

5 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरीकरण, औद्योगीकरण और धार्मिक विरासत स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिये 33,769 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया।

### प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया।

नोट :

- 33,769 करोड़ रुपए के कॉर्पस में से 14,000 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिये आवंटित किये गए हैं। अगले वर्ष फरवरी में होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के लिये 56 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।
- पूरक बजट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिये कॉर्पस के साथ, सरकार ने कहा कि इसका लक्ष्य राज्य में 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिये, सरकार का मार्गदर्शन करने के लिये नियुक्त परामर्श एजेंसी को 35 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
- राज्य सरकार ने इस बजट में 'नए शहरों'के बुनियादी ढाँचे और समग्र विकास के लिये 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
- पर्यटन, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, स्टार्टअप और औद्योगिक पार्कों की स्थापना जैसे क्षेत्रों के लिये घोषित नई नीतियों के तहत दिये गए प्रोत्साहनों के लिये भी धन आवंटित किया जाएगा।
- औद्योगिक पार्क स्थापित करने में निवेश करने वाले निवेशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 300 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया जाएगा, जबकि 100 करोड़ रुपए स्टार्टअप की स्थापना से जुड़े प्रोत्साहन के लिये रखा गया है।
- पूरक बजट में स्मार्ट सिटी मिशन के लिये 899 करोड़ रुपए तथा नई सौर नीति 2022 के तहत सौर शहर स्थापित करने की सरकार की योजना के अनुरूप अयोध्या सौर शहर के विकास के लिये 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- अपने पूरक बजट में, सरकार ने नई घोषित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सब्सिडी के लिये 100 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं, जबकि 1,000 नई बसों की खरीद के लिये 200 करोड़ रुपए, राज्य में ईको टूरिज्म विकसित करने के लिये 20 करोड़ रुपए और कुकरैल नाइट सफारी विकसित करने के लिये एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
- बजट में उत्तर प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ऋण देने के लिये 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बिजली क्षेत्र में परियोजनाओं और योजनाओं के वित्तपोषण के लिये 5,900 करोड़ रुपए अलग रखे जाएंगे।
- उत्तर प्रदेश के चार शहरों- वाराणसी, नोएडा, आगरा और लखनऊ में अगले साल जी-20 लीडरशिप समिट के कार्यक्रमों की मेजबानी की जानी है, इन आयोजनों के लिये पूरक बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सूचना एवं संचार सेवाओं के विकास के लिये बजट में 804 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में सड़कों के निर्माण एवं रैंपिंग के लिये 2337 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, गन्ना विकास परिषद द्वारा निर्मित सड़कों के विकास के लिये 155 करोड़ रुपए अलग रखे जाएंगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के तहत स्टेडियम और ओपन जिम बनाने और विकसित करने के लिये 15 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं।
- पूरक बजट में कृषि ऋण सब्सिडी के लिये 190 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है।
- आध्यात्मिक पर्यटन के लिये अपने प्रयास को जारी रखते हुए, सरकार ने नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र में सड़कों और सुविधाओं के विकास जैसे धार्मिक आकर्षण के आसपास के स्थानों को विकसित करने के लिये 5 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है।

## गंगा बेसिन में लागू होगा गंगा मित्रों का मॉडल

### चर्चा में क्यों ?

6 दिसंबर, 2022 को महामना मालवीय गंगाशोध केंद्र के चेयरमैन व पर्यावरण वैज्ञानिक प्रो. बीडी त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गंगा की अविरलता को धार देने के लिये गंगा मित्रों का मॉडल पूरे गंगा बेसिन में लागू किया जाएगा। इसके लिये प्रयागराज से बलिया तक 315 किलोमीटर लंबे गंगा क्षेत्र में गंगा मित्र जनता को गंगा के सरोकारों से जोड़ा जाएगा।

### प्रमुख बिंदु

- प्रो. बीडी त्रिपाठी ने बताया कि 'नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा' के तहत अविरल, निर्मल, अर्थ, आध्यात्मिक एवं पारिस्थितिक गंगा से जन-जन को जोड़ने की कवायद का 10 महीने में ही सकारात्मक असर नज़र आ रहा है। महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र बीएचयू ने इस मॉडल को पूरे गंगा बेसिन में लागू करने का प्रस्ताव भेजा है।
- उल्लेखनीय है कि मार्च से 'गंगा संरक्षण अभियान' की शुरुआत हुई थी। 700 गंगा मित्र अभियान से जुड़े हैं। 90 लाख की लागत से प्रयागराज से बलिया के बीच 21 किलोमीटर के अंतराल पर गंगा जागरूकता शोध केंद्र स्थापित किये गए हैं। गंगा मित्रों ने 650 से अधिक गंगा ग्राम एवं सौ गंगा वार्ड का चयन कर 15 हज़ार जल संरक्षण समिति एवं 15 हज़ार जल संरक्षक सदस्य बनाए हैं।

नोट :

- उन्होंने बताया कि इस अभियान से आम आदमी भी जुड़ रहे हैं। गंगा किनारे रहने वालों की सोच व कार्यशैली में गंगा मित्रों के प्रयास से काफी बदलाव आया है। इस प्रोजेक्ट को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को भेजा गया है। इसे गंगा बेसिन के 2525 किलोमीटर के दायरे में लागू करने की योजना है। दूसरी अन्य नदियों के संरक्षण के लिये भी योजना को मूर्तरूप दिया जा सकता है।
- इसके लिये पाँच बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा-
  - स्वच्छ गंगा: स्वच्छ गंगा अभियान को गंगा मित्र धार दे रहे हैं। गंगा स्वच्छता के लिये आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
  - अविरल गंगा: अविरल गंगा के लिये गंगा मित्र लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
  - आध्यात्मिक गंगा : 75 गंगा चौपालों से 4500 महिलाओं और 150 स्कूलों के 10500 बच्चों में संस्कार डालकर नमामि गंगे से जोड़ा गया है।
  - अर्थ गंगा: 75 गंगा ग्रामों के किसानों को गंगाजल के नाम कंजपटिव उपभोग, वर्मी कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक फॉर्मिंग, सब्जियों एवं फलों की गंगा ब्रांडिंग तथा नवीन सिंचाई की पद्धति की तकनीक की जानकारी देकर उनकी आय में बढ़ोतरी कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
  - पारिस्थितिक विकास: 150 स्कूल, नदियों, तालाब के किनारे, पार्कों एवं मंदिरों के आसपास पौधरोपण एवं जलीय जीवों के संरक्षण के लिये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इको स्किल्ड तकनीकी के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।
- ज्ञातव्य है कि गंगा नदी गोमुख से निकलती है, जो पाँच राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। नदी का पानी जिस क्षेत्र से होकर गुज़रता है, उसेही बेसिन कहते हैं। गंगा का बेसिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में है।

## उत्तर प्रदेश में बनेंगे एकीकृत न्यायालय परिसर

### चर्चा में क्यों ?

6 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के बड़ौदा में बने एकीकृत न्यायालय परिसर की तर्ज पर राज्य के दस ज़िलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा से पास अनुपूरक बजट के माध्यम से इस विशेष परियोजना के लिये 400 करोड़ रुपए दिये गए हैं।

### प्रमुख बिंदु

- एकीकृत न्यायालय परिसर के लिये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के जिन 10 ज़िलों का चयन किया है, वे हैं- महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यों में अपराधों की अलग-अलग प्रकृति के अनुसार त्वरित न्याय के लिये अलग-अलग कानूनों से जुड़े अदालतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बहुत से जगहों पर किराये के भवनों में अदालतों के चलते न्यायिक अधिकारियों और फरियादियों दोनों को ही दिक्कत होती है। सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में भी दिक्कतें आती हैं। इसको देखते हुए अदालतों के लिये एकीकृत कोर्ट परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- इसके अलावा एक आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ऐसे न्यायालय परिसरों के निर्माण का आदेश दिया गया है।
- राज्य में मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोक निर्माण, गृह तथा विधि एवं न्याय विभाग इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। एकीकृत भवन में कोर्ट, जजों के चैंबर, मीटिंग हॉल, विडियो कोर्ट, पॉर्किंग, कैंटीन सहित सभी सुविधाओं के लिये जगह होगी।
- राज्य में 10 ज़िलों में बनने जा रहे इस एकीकृत अदालत परिसर में ज़िला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, विविध, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत आदि होंगें। यहाँ न्यायालय भवन, अधिवक्ता चैंबर, सभागार के अलावा न्यायधीशों और न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय कॉलोनी, पार्किंग और फूड प्लाजा भी होगा।

नोट :

## उत्तर प्रदेश के 6 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के टेंडर जारी

### चर्चा में क्यों ?

8 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि राज्य में 'एक ज़िला, एक मेडिकल कॉलेज'के तहत 6 ज़िलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये टेंडर जारी किया गया है।

### प्रमुख बिंदु

- टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये निवेशकों को चयनित किया जाएगा।
- विदित है कि केंद्र सरकार की वायबलिटी गैप फंडिंग स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के इन 6 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई है।
- चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये टेंडर जारी किया है। टेंडर का डिटेल जेम पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया है।
- उन्होंने बताया कि 6 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोलने में करीब 1525 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें से केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में करीब 1012 करोड़ रुपए का भार उठाएगी। एक कॉलेज को औसतन 160 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
- राज्य के महाराजगंज और शामली में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये निवेशकर्त्ता का चयन का कार्य शुरू हो गया हैं। अगले साल तक महाराजगंज में उपचार शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा शामली और मऊ में मेडिकल कॉलेज प्रक्रियाधीन है।
- प्रमुख सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आम लोगों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में यह बड़ा कदम है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने से राज्य के धन की बचत होगी।
- उन्होंने बताया कि राज्य ज़िला अस्पताल और भूमि 33 साल की लीज पर देगी। इसके बाद निवेशकर्त्ता मेडिकल कॉलेज सरकार को वापस कर देगा। यह राज्य की संपत्ति होगी और साथ ही स्टांप ड्यूटी में छूट और उपकरण सब्सिडी भी देगी।

## ओडीओपी की तर्ज पर 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन वेटलैंड' की तैयारी

### चर्चा में क्यों ?

9 दिसंबर, 2022 को प्रदेश के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन एवं जंतु उद्यान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना ने जानकारी दी कि सरकार ने प्रदेश में 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' की तर्ज पर अब 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन वेटलैंड' पर काम करने का फैसला किया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए हैं।

### प्रमुख बिंदु

- राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि इस योजना के तहत हर जनपद में एक वेटलैंड को सँवारने का काम किया जाएगा, जिससे वह पर्यटन के लिहाज से आकर्षण का केंद्र बन सके।
- प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक जनपद में एक वेटलैंड को इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जाए, जिससे पर्यटन के मानचित्र में इस वेटलैंड को खास स्थान मिल सके। इससे प्रदेश के इको टूरिज्म का दायरा और व्यापक होगा। सरकार की इस पहल से अभी तक जो वेटलेंड उपेक्षित स्थिति में हैं या जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया है, उनका कायाकल्प हो सकेगा।
- इसके साथ ही राजधानी लखनऊ के कुकरैल में प्राणि उद्यान को शिफ्ट करने और नाइट सफारी का काम जल्द शुरू होगा। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के अंत तक कुकरैल जू एवं नाइट सफारी की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है और लखनऊ चिड़ियाघर का अगला स्थापना दिवस कुकरैल में मनाए जाने का निर्णय किया गया है।
- वन मंत्री ने वन ट्रिलियन इकॉनामी के संबंध में वन विभाग को दिये गए दस हज़ार करोड़ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रदेश में लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये जनपदवार लक्ष्यों को निर्धारण करने के निर्देश दिये। साथ ही काष्ठ कला बोर्ड की स्थापना के संबंध में चर्चा की गई।
- उन्होंने बरेली में जू स्थापना के प्रगति की जानकारी ली। वहीं सांडी नवाबगंज समसपुर पक्षीविहार, सारनाथ डियर पार्क, इंदिरा गांधी वनस्पति उद्यान, रायबरेली के बेहतर प्रबंधन के लिये सोसायटी-ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

नोट :

## 'पहचान' से एक क्लिक पर खुलेगी माध्यमिक स्कूलों की कुंडली

### चर्चा में क्यों ?

11 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के हाथरस की ज़िला विद्यालय निरीक्षक रीतू गोयल ने बताया कि सीबीएसई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालयों की भी अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी कॉलेजों की वेबसाइट बनवाई गई है। इसे 'पहचान' नाम दिया गया है। एक क्लिक पर विद्यालय से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

### प्रमुख बिंदु

- रीतू गोयल ने बताया कि माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन के तहत प्रदेश सरकार के निर्देश पर बोर्ड ने स्कूलों का वेब पेज अपनी वेबसाइट पर 'पहचान' नाम से अपलोड कर दिया है।
- इसका उद्देश्य लोगों को उनके क्षेत्र के स्कूलों के विषय में जानने-पहचानने का अवसर देने के साथ ही उसके उत्कर्ष में योगदान के लिये प्रेरित करना भी है। स्कूलों के वेब पेज बनवाने का काम मुख्यमंत्री की 100 दिन की कार्य योजना में भी शामिल था।
- अब उत्तर प्रदेश बोर्ड से जुड़े राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन स्कूलों की कुंडली एक क्लिक पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
- उन्होंने बताया कि स्कूल से जुड़ी हर जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। स्कूल की मान्यता का वर्ष, गूगल लोकेशन, ज़िला मुख्यालय से दूरी, सुविधाएँ, छात्रों-शिक्षकों के आँकड़े, पाँच साल की बोर्ड परीक्षा के आँकड़े, दस साल के रिजल्ट और पंजीकरण की ग्राफ प्रस्तुति, स्कूल की उपलब्धियाँ, छात्रों के पंजीकरण की सुविधा, महत्त्वपूर्ण अवस्थापना सुविधा, महत्त्वपूर्ण हाइपर लिंक आदि सूचनाएँ उपलब्ध हैं।
- पोर्टल पर प्रत्येक स्कूल का पहचान रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध है। पहचान रिपोर्ट कार्ड में राज्य व ज़िले स्तर पर रैंकिंग की जानकारी भी दी गई है। इसमें स्कूल की राज्य और ज़िले स्तर पर रैंकिंग के साथ ही सात स्टार में से रेटिंग, छह बिंदुओं पर ग्रेडिंग दी गई है।

## प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया

### चर्चा में क्यों ?

11 दिसंबर, 2022 को गोवा में 9वें विश्व आयुर्वेद कॉन्ग्रेस (डब्ल्यूएसी) के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया।

### प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही समारोह में प्रधानमंत्री ने डिजिटल माध्यम से आयुर्वेद और होम्योपैथी के दो राष्ट्रीय आयुष संस्थान- गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का भी उद्घाटन किया।
- उल्लेखनीय है कि एम्स की तर्ज पर बने गाजियाबाद का कमला नेहरू नगर स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल है। यहाँ पर मरीजों के लिये 200 बेड की सुविधा है।
- इस संस्थान में यूनानी पद्धति से मरीजों का इलाज किया जाएगा। इससे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई सुविधा मिलेगी। इस संस्थान में 14 विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों का इलाज करेंगे।
- राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान के बनने से गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर और मेरठ जैसे शहरों से मरीज यहाँ आकर अपना इलाज करा सकेंगे। अस्पताल कैंपस में डॉक्टर और कर्मचारियों का रेसिडेंस भी बनाया गया है।
- यह यूनानी हॉस्पिटल करीब 10 एकड़ ज़मीन पर 381 करोड़ की लागत से बना है। इसका शिलान्यास वर्ष 2019 में तत्कालीन केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री श्रीपद नाइक और केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह ने किया था।
- इस संस्थान में बच्चों और महिलाओं के लिये पीकू-नीकू वार्ड हैं। संस्थान में पाँच ऑपरेशन थिएटर, मेटरनिटी विंग, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, आईसीयू, एक्यूप्रेशर कक्ष, फिजियोथेरेपी कक्ष, पंचकर्म कक्ष, जिम्नेजियम, सीएसएसडी, कैंटीन, शैक्षणिक और प्रशासनिक ब्लॉक, ट्यूटोरियल रूम, सेमिनार हॉल, म्यूजियम, लाइब्रेरी, लैब, बहुउद्देश्यीय शोध विभाग, यूनानी फार्मेसी जैसी सुविधाएँ हैं। इसके अलावा यहाँ मरीज स्टीम बाथ, हिप बाथ, सोना बाथ जैसी सुविधाएँ भी ले सकेंगे।

नोट :

- संस्थान में अभी ओपीडी में मरीजों का इलाज होगा, वर्ष 2023 से यूनानी विधा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस संस्थान में 14 विभाग होंगे। यहाँ यूनानी पद्धति में परास्नातक और शोध की शिक्षा भी मिलेगी। इनमें औषधि विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा मूल्यांकन, यूनानी चिकित्सा और प्रथाओं के वैज्ञानिक सत्यापन पर ध्यान केंद्रित रहेगा।
- संस्थान श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश, उजबेकिस्तान व अन्य देशों के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के साथ यूनानी पद्धति का प्रचार प्रसार भी करेगा। इसमें यूनानी दवाओं पर विभिन्न तरह के शोध किये जाएंगे। यहाँ यूनानी पद्धति में परास्नातक और पीएचडी की शिक्षा भी दिलाई जाएगी।

## यमुनापार क्षेत्र में 624 करोड़ की योजना स्वीकृत

### चर्चा में क्यों ?

11 दिसंबर, 2022 को केंद्रीय कानून राज्यमंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा के यमुनापार क्षेत्र के निवासियों की पानी की समस्या खत्म करने के लिये केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त योजना 'हर घर जल' के तहत यमुनापार क्षेत्र में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिये 624 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत दी गई है।

### प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय कानून राज्यमंत्री ने बताया कि आगरा के यमुनापार क्षेत्र को योजना के लिये दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग ट्रांस यमुना ज़ोन है, जिसमें सीता नगर, शाहदरा, एत्माद्दौला, प्रकाश नगर, नवल गंज, कछपुरा और पीला खार क्षेत्र शामिल हैं। वहीं, दूसरा ज़ोन ट्रांस यमुना ज़ोन 2 बनाया गया है, जिसमें ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस वन, नराइच, नगला जमुनी, नगला रामबल, कालिंदी विहार, नाउ की सराय, रवि नगर, फाउंड्री नगर और इस्लाम नगर शामिल किये गए हैं।
- उन्होंने बताया कि यमुनापार क्षेत्र में वाटर वर्क्स की जो योजना स्वीकृत की गई है, उसके तहत क्षेत्र में 44 एमएलडी पानी की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 2040 तक जनसंख्या लगभग 4000000 हुई तो पानी की मांग 73 एमएलडी होगी। वहीं, अगर 2055 तक जनसंख्या 600000 हुई तो पानी की मांग बढ़कर 107 एमएलडी हो जाएगी। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए इस योजना को तैयार किया गया है, जिससे भविष्य में वाटर वर्क्स की 80 एमएलडी की क्षमता को बढ़ाया जा सके।
- प्रेस वार्ता में मौजूद एत्मादपुर के विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने बताया कि यमुनापार क्षेत्र में वाटर वर्क्स बनाने के लिये पोइया घाट पर जमीन चिन्हित की गई है तथा इस योजना की प्लानिंग वर्ष 2055 तक की जनसंख्या के अनुसार की गई है।
- इस योजना से एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 300000 परिवारों को फायदा होना निश्चित है। इस वाटर वर्क्स के अंतर्गत 3 जलाशय, 14 नए ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे और इस योजना को 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।

## उत्तर प्रदेश रोज़गार देने में देश में अव्वल

### चर्चा में क्यों ?

12 दिसंबर, 2022 को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) में उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। मानव दिवस सृजन में और 100 दिवस का पूर्ण रोज़गार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

### प्रमुख बिंदु

- ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये रोज़गार सृजन के तहत वार्षिक लक्ष्य 2600 लाख मानव दिवस के मुकाबले 62 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश ने 7809.74 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश ने 53 लाख परिवारों को रोज़गार दिया है। यही नहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,77,878 परिवारों को 100 दिवस का पूर्ण रोज़गार उपलब्ध कराया गया है और 100 दिवस का पूर्ण रोज़गार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।
- उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मनरेगा अभिसरण (कन्वर्जेंस) के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों के लिये लाइन विभागों की प्रभावी सहभागिता व फील्ड स्तर पर अभिसरण की आवश्यकता के मद्देनज़र ठोस कदम उठाएँ। इसके साथ ही मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत प्रगति बढ़ाई जाए।

नोट :

- गौरतलब है कि मनरेगा अभिसरण (कन्वर्जेंस) के तहत वर्ष 2022-23 में 97 करोड़ रुपए का वित्तीय लक्ष्य रखा गया है।
- मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत श्रम, एसआरएलएम, भूगर्भ जल विभाग, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, उद्यान, परती भूमि विकास, बेसिक शिक्षा, पशुपालन, युवा कल्याण, रेशम, कृषि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, बाल विकास एवं पुष्टाहार, ग्रेटर शारदा सहायक, ग्रामीण अभियंत्रण डेरी, सिंचाई, लघु सिंचाई आदि लगभग 24 से अधिक विभागों द्वारा कार्य कराया जाता है।
- उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मनरेगा के तहत जिन श्रमिकों ने 90 दिन मनरेगा में कार्य किया है, उन्हें बीओसीडब्ल्यू बोर्ड (श्रम विभाग) में पंजीकरण कराते हुए श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाए।

## उत्तर प्रदेश में 5 हज़ार एकड़ में बनेगी नॉलेज स्मार्ट सिटी

### चर्चा में क्यों ?

18 दिसंबर, 2022 को सैन फ्राँसिस्को में आस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिये एमओयू साइन किया।

### प्रमुख बिंदु

- सैन फ्राँसिस्को में यूएस बेस्ड सलोनी हार्ट फाउंडेशन ने राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार की मौजूदगी में एमओयू साइन किया। वहीं आस्टिन यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिये 35 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू साइन किया।
- यह नॉलेज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पाँच हज़ार एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा, इसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों का समावेश होगा।
- गौरतलब है कि राज्य की योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ में 10-12 फरवरी के मध्य होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के ज़रिये 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और अधिकारियों की 8 टीमों को 18 देशों में रोड शो और ट्रेड शो के ज़रिये निवेश आकर्षित करने के लिये भेजा है।
- इससे पहले स्वीडन बिज़नेस कम्युनिटी ने उत्तर प्रदेश में गहरी दिलचस्पी दिखाते हुए कुल 15000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। प्रदेश में निवेश आने से अलग-अलग क्षेत्रों में तो विकास होगा ही, साथ ही रोज़गार भी बढ़ेगा।
- उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाली ये कंपनियाँ यहाँ फिल्म सिटी, रिटेल, टूरिज्म, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में पैसा लगाने के लिये तैयार हैं। स्वीडन के अलावा कनाडा के वैंकूवर से भी टीम योगी को 1200 करोड़ रुपए के छह एमओयू (MOU) प्राप्त हुए हैं।
- स्टॉकहोम में रोड शो के दौरान आयोजित विभिन्न बी2जी और जी2जी बैठकों में रक्षा, कपड़ा और वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश को लेकर चर्चा की गई।

## उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भी खुलेंगे जेनेरिक आधार के स्टोर

### चर्चा में क्यों ?

18 दिसंबर, 2022 को जेनेरिक आधार के संचालक अर्जुन देशपांडे ने बताया कि जेनेरिक आधार के मेडिकल स्टोर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भी खोले जाएंगे। ग्रामीण इलाकों तक जेनेरिक दवाएँ पहुँचाने के लिये जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार और जेनेरिक आधार के बीच एमओयू होगा।

### प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि जेनेरिक आधार के संचालक अर्जुन देशपांडे ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और बताया कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक आधार के ज़रिये मरीज़ों को सस्ती दर पर दवाएँ दी जा सकेंगी।

नोट :

- उन्होंने बताया कि जेनेरिक आधार के करीब 1800 स्टोर चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में 150 स्टोर हैं। मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद इसे बढ़ाकर अब 700 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। जहाँ यह जेनेरिक स्टोर होगा, उससे करीब पाँच सौ मीटर दूर ही दूसरा स्टोर खोला जाएगा।
- उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक आधार के मेडिकल स्टोर चल रहे हैं। मरीज़ों को सस्ती दर पर दवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

## आईएचआरसी का 63वाँ सत्र उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार में आयोजित

### चर्चा में क्यों ?

18-19 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार, लखनऊ में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति (आईएचआरसी) के 63वें सत्र का आयोजन किया गया।

### प्रमुख बिंदु

- आईएचआरसी के 63वें सत्र का उद्घाटन दया शंकर सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 दिसंबर को किया गया।
- सत्र के दौरान भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के संग्रह से मूल अभिलेखीय स्रोतों के आधार पर 'स्वतंत्रता की गाथा: ज्ञात और अल्प ज्ञात संघर्षों'नामक एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया।
- दो दिवसीय सत्र में पहले दिन उद्घाटन और व्यावसायिक सत्र और अगले दिन शैक्षणिक सत्र का आयोजन किया गया। विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास में 1600 ई. के पश्चात् के मूल स्रोतों पर आधारित कुल 24 शोधपत्र इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुत किया गया।
- भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति (आईएचआरसी) अभिलेखों के रचनाकारों, संरक्षकों और उपयोगकर्त्ताओं का एक अखिल भारतीय मंच है जिसकी स्थापना 1919 में अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिये उनके उपयोग से जुड़े सभी मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिये की गई थी।
- नई दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति (1911 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के तौर पर फिर से नामित) का सचिवालय है।
- आईएचआरसी की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं और इसमें 134 सदस्य शामिल हैं जिनमें भारत सरकार की एजेंसियाँ, भारत सरकार के नामांकित व्यक्ति, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के अभिलेखागार, विश्वविद्यालयों और विद्वान संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। आईएचआरसी ने अब तक 62 सत्र आयोजित किये हैं।
- समिति के दो सहायक निकाय हैं, (i) समितियों के सत्रों में प्रस्तुत करने के लिये अभिलेखीय स्रोतों के आधार पर कागजात की जाँच एवं अनुमोदन करने के लिये संपादकीय समिति और (ii) स्थायी समिति अपनी सिफारिशों पर समिति द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने और इसके बारे में समिति की बैठक के एजेंडे पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये। संस्कृति मंत्रालय के सचिव आईएचआरसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

## वाराणसी में बनेगा ओडीओपी मॉल

### चर्चा में क्यों ?

20 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश उद्योग के संयुक्त आयुक्त उमेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के वाराणसी के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में चार मंजिला ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट) मॉल निर्माण का प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गए हैं।

### प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि वाराणसी के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में करीब दो एकड़ क्षेत्र में फैले पार्क में ओडीओपी मॉल प्रस्तावित है। इस पार्क में पहले उद्योगों के लिये कोयला स्टोरेज होता था और यहाँ फ्लैटेड फैक्ट्री बनाने की भी योजना बनी थी।

नोट :

- ओडीओपी मॉल के शहर में होने की वजह से यहाँ ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे बुनकरों, शिल्पियों को माल भाड़ा में राहत मिलेगी।
- उमेश कुमार सिंह ने बताया कि उद्योग विभाग ओडीओपी मॉल में बुनकरों, शिल्पियों और निर्यातकों को लीज पर जगह देगा। एकमुश्त रकम देकर बुनकर व शिल्पी वहाँ लंबे समय तक रह सकेंगे। इससे किराया आदि के खर्च में बार-बार फेरबदल के झंझट से निजात मिलेगी।
- ओडीओपी मॉल के निर्माण से सिल्क उत्पादों, मीनाकारी और लकड़ी के खिलौनों के कारोबार को प्रोत्साहन मिलेगा। मॉल का सबसे ज्यादा लाभ वाराणसी के चौक क्षेत्र के साड़ी व्यावसायियों को मिलेगा।

## सामाजिक प्रगति करने में 31वें स्थान पर उत्तर प्रदेश

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने एक सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश के प्रत्येक राज्य को सामाजिक प्रगति के मामले में एक रैंक दी गई है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को 31वाँ स्थान मिला है।

### प्रमुख बिंदु

- ईएसी-पीएम की सामाजिक प्रगति सूचकांक को तैयार करने के लिये काउंसिल ने 3 आयाम और इनके 12 अवयवों को आधार बनाया है। पहला आयाम 'बुनियादी मानवीय आवश्यकताएँ'हैं। इसमें चार अवयव (i) पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल, (ii) पानी और सफाई व्यवस्था, (iii) आश्रय और (iv) व्यक्तिगत सुरक्षा शामिल हैं।
- दूसरा आयाम कल्याण की नींव है, इसमें शामिल चार अवयव (i) बुनियादी ज्ञान तक पहुँच, (ii) सूचना और संचार तक पहुँच, (iii) स्वास्थ्य और कल्याण और (iv) पर्यावरणीय गुणवत्ता हैं।
- इसी प्रकार तीसरा आयाम चुनौती है, जिसमें अवयवों के रूप में (i) व्यक्तिगत अधिकारों, (ii) व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, (iii) समावेशिता और (iv) उन्नत शिक्षा तक पहुँच को शामिल किया गया है।
- इन तीनों आयामों और अवयवों में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन औसतन सामान्य ही रहा। केवल दो अवयवों- पेयजल की उपलब्धता और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास प्रदान करने में राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है।
- जनसंख्या की दृष्टि से देश में पहले स्थान पर आने वाला उत्तर प्रदेश सामाजिक प्रगति सूचकांक में 16 प्वाइंट लेकर 31वें स्थान पर आया है।
- इस इंडेक्स में पहले स्थान पर पांडिचेरी को 99 प्वाइंट मिले हैं, वहीं अंतिम पायदान पर आने वाले राज्य झारखंड को 43.95 प्वांइट मिला है।
- इंडेक्स की रैंकिंग को 6 स्तरों में बाँटा गया है, जिनमें सबसे पहला स्तर अति उच्च सामाजिक प्रगति, दूसरा उच्च सामाजिक प्रगति, तीसरा ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, चौथा निम्न मध्य सामाजिक प्रगति, पाँचवा निम्न सामाजिक प्रगति और छठवाँ बहुत कम सामाजिक प्रगति स्तर है। सामाजिक प्रगति के इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश पाँचवें निम्न सामाजिक प्रगति स्तर पर पहुँचा है। उत्तर प्रदेश के साथ इस स्तर में शामिल ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्य भी शामिल हैं।
- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के साथ भारत के राज्यों और ज़िलों के लिये सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया। यह रिपोर्ट 2015-16 के बाद से कुछ प्रमुख संकेतकों के प्रदर्शन में बदलाव का मूल्यांकन करके भारत में सामाजिक प्रगति की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करती है।
- इसके अलावा, रिपोर्ट देश के 112 आकांक्षी ज़िलों द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डालती है, जिससे उन्हें अपने सामाजिक प्रगति पर नज़र रखने और उन क्षेत्रों को समझने में मदद मिलती है, जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

नोट :

## रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के लिये लखनऊ में आधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंज़ूरी दी

### चर्चा में क्यों ?

22 दिसंबर, 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिये लखनऊ में एक आधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंज़ूरी दी। कमांड अस्पताल एक ग्रीन फील्ड बहुमंज़िला अस्पताल होगा, जिसमें 780 भर्ती मरीज बेड के साथ-साथ 100 क्राइसिस एक्सपेंशन बेड के लिये तकनीकी सुविधा की व्यवस्था होगी, ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके।

### प्रमुख बिंदु

- मध्य भारत में आधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण से सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ेगा और कर्मियों को वांछित सहायता मिलेगी।
- मौजूदा कमांड अस्पताल लखनऊ सशस्त्र बलों का सबसे व्यस्त अस्पतालों में से एक है जो 22 सैन्य अस्पतालों, दो वायु सेना अस्पतालों और 109 पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिक के लिये एक तृतीयक देखभाल रेफरल अस्पताल है।
- यह मध्य भारत के छह राज्यों के साथ-साथ नेपाल में फैले 5 लाख से अधिक आश्रित ग्राहकों की स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा करता है। अस्पताल के बिस्तर हमेशा 80% से अधिक भरे होते हैं।
- दवाओं और सर्जरी की सभी सुपर स्पेशियलिटी के लिये तृतीयक देखभाल केंद्र होने के अलावा, अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिये घातक रोग उपचार केंद्र (एमडीटीसी) भी है। अस्पताल प्रशिक्षुओं, स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं, एमएनएस कैडेटों और नर्सिंग सहायकों को भी प्रशिक्षित करता है।
- मौजूदा अस्पताल में मरीजों की संख्या को देखते हुए रक्षा मंत्री ने 94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की एक विशेष परियोजना को मंज़ूरी दी। कमांड अस्पताल, लखनऊ की योजना देश में लागू नवीनतम इमारत कोड और अस्पताल नियमों के अनुरूप बनाई गई है।
- यह प्रगतिशील रोगी देखभाल सेवाओं के लिये ज़ोन के अनुसार नियोजित किया गया है जो रोगी की आवाजाही को कम और नियंत्रित करता है, अस्पताल के संक्रमण (एचएआई) को कम करता है, नियोजित बायोमेडिकल वेस्ट (बीएमडब्ल्यू) अलगाव और निपटान, सभी विकलांग अनुकूल सेवाओं के साथ आपात स्थिति में आपदा निकासी योजना, निदान और चिकित्सीय दोनों के लिये विकिरण का सुरक्षित उपयोग अस्पताल में शामिल कई आधुनिक विशिष्टताओं में से शामिल हैं।
- डेटा और ऊर्जा संरक्षण पर तेजी से पहुँच के लिये भवन प्रबंधन प्रणाली के साथ-साथ अस्पताल सूचना प्रणाली जैसी एकीकृत सेवाओं को भी परियोजना में शामिल किया गया है।

## सीसीआरएएस-सीएआरआई, झाँसी को एनएबीएल की मान्यता

### चर्चा में क्यों ?

22 दिसंबर, 2022 को आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) के तहत प्रमुख संस्थान केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झाँसी को एनएबीएल की आधिकारिक मान्यता मिल गई।

### प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झाँसी (उत्तर प्रदेश) सीसीआरएएस, आयुष मंत्रालय के प्रमुख संस्थानों में से एक है, जिसमें अत्याधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ (रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, फार्माकोग्नॉसी), आयुर्वेदिक फार्मेसी, सेंट्रल हर्बेरियम और संग्रहालय एवं नेशनल रॉ ड्रग्स रिपॉजिटरी (एनआरडीआर) हैं।
- केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झाँसी के अलावा केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई), नई दिल्ली को एनएबीएच की आधिकारिक मान्यता मिली है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली एनएबीएच की आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने वाला सीसीआरएएस के तहत पहला संस्थान है।

नोट :

- इन दो सीसीआरएएस संस्थानों के अलावा, पंचकर्म के लिये राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (एनएआरआईपी), चेरुथुरुथी, त्रिशूर, केरल को भी अपनी नैदानिक प्रयोगशाला सेवाओं के लिये एनएबीएल एम (ईएल) टी की आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। एनएआरआईपी, केरल केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं में से एक है।
- उल्लेखनीय है कि एनएबीएच भारतीय गुणवत्ता परिषद का मूल बोर्ड है, जिसकी स्थापना स्वास्थ्य सेवा संगठनों के मान्यता कार्यक्रमों को स्थापित करने और उन्हें चलाने के लिये की गई है। आधिकारिक मान्यता राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर रोगी सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती है।

## देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी मिर्जापुर की सानिया मिर्ज़ा

### चर्चा में क्यों?

22 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर ज़िले के छोटे से गाँव की रहने वाली सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा में 149वीं रैंक के साथ फ्लाइंग विंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। एनडीए से पास आउट होकर सानिया देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन सकती हैं।

### प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि अबकी बार फ्लाइंग विंग में दो ही सीट हैं। एनडीए में मात्र 19 पद महिलाओं के लिये आरक्षित हैं। सब कुछ ठीक रहा तो एनडीए से पास आउट होकर सानिया को देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि सानिया मिर्जापुर देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे से गाँव जसोवर की रहने वाली हैं। प्राइमरी से लेकर 10वीं तक की शिक्षा गाँव के ही पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज से पूरी की। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में ज़िला टॉपर भी रही हैं। इसके बाद सानिया ने शहर के गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी की।
- सानिया ने बीते 10 अप्रैल को एनडीए की परीक्षा दी। नवंबर में जारी लिस्ट में उनका चयन हुआ है। वे फ्लाइंग में चुनी जाने वाली दो महिलाओं में से एक हैं। वह एनडीए ट्रेनिंग के लिये 27 दिसंबर को पुणे में ज्वाइन करेंगी।

## राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में यातायात विस्तार

### चर्चा में क्यों?

23 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष कार्याधिकारी सुधांशु पंत ने वाराणसी के सर्किट हाउस में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में यातायात विस्तार पर आयोजित ट्रेड मीट में बताया कि देश के सबसे लंबे जलमार्ग वाराणसी से डिब्रूगढ़ (बोगीबील) तक जनवरी, 2023 से मालवाहक जहाज़ों का संचालन शुरू हो जाएगा।

### प्रमुख बिंदु

- सुधांशु पंत ने बताया कि भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण वाराणसी-गाजीपुर-मझऊआं-बाढ़ जलमार्ग को पटना-फरक्का जलमार्ग की तर्ज़ पर तैयार करेगा। इस जलमार्ग पर जहाज़ों के 24 घंटे सुगम यातायात के लिये नाइट नेविगेशन सिस्टम भी विकसित किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि मालवाहक जहाज़ों के वाराणसी से संचालन से पूर्वांचल के जीआई उत्पादों के निर्यात को जलमार्ग से जोड़कर इसे बढ़ावा देने की पहल की जाएगी। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 का ज़्यादा-से-ज्यादा उपयोग किये जाने के लिये केंद्र और राज्य सरकार के विभागों की ओर से सुझाव लेकर जलमार्ग प्राधिकरण अपनी कार्ययोजना तैयार करेगा।
- बैठक में राज्य के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि विभिन्न प्रकार के अनाज वाराणसी से निर्यात होते हैं, जिसके लिये जलमार्ग का उपयोग जल्द ही किया जाएगा। इसके साथ ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को निर्यात होने वाले उत्पाद तथा उनके मार्गों का विवरण उपलब्ध हो सके तो वाराणसी जलमार्ग से निर्यात किया जाना और भी समृद्ध होगा।
- इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन के प्रतिनिधि ने जलमार्ग के ज़रिये खाद व यूरिया का निर्यात समय से कराने के लिये गंगा में 24 घंटे जहाज़ों के संचालन का सुझाव दिया। जलमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई।

नोट :

- जलमार्ग प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जयंत सिंह ने बताया कि वाराणसी-कोलकाता जलमार्ग वर्ष में 300 दिन संचालन के लिये उपलब्ध है। यह गंगा विलास वाराणसी के पर्यटन को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें 10 जनवरी से 13 जनवरी तक गंगा विलास के यात्रियों को काशी दर्शन कराया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि अप्रैल से काशी के घाटों को जोड़ते हुए सोलर वाटर टैक्सी के संचालन की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगले महीने इसकी निविदा जारी की जाएगी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर इसका संचालन किया जाएगा। वाराणसी-कोलकाता व डिब्रूगढ़ जलमार्ग को विकसित करने के लिये विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

## 336 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा काशी इंटर मॉडल स्टेशन

### चर्चा में क्यों ?

25 दिसंबर, 2022 को उत्तर रेलवे मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुरेश कुमार सपरा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन को मेजर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिये टेंडर जारी किया गया है। करीब 336 करोड़ रुपए की इस परियोजना से काशी इंटर मॉडल स्टेशन बन जाएगा।

### प्रमुख बिंदु

- सुरेश कुमार सपरा ने बताया कि इस परियोजना से काशी इंटर मॉडल स्टेशन बनने के साथ-साथ यहाँ यार्ड रीमॉडलिंग, कॉम्प्लेक्स और होटल निर्माण समेत कई कार्य किये जाएंगे। यहाँ टेक्नो फिजिबिलिटी सर्वे का काम पहले ही पूरा हो गया है। अगले साल दिसंबर तक डीपीआर का काम भी हो जाएगा।
- इस परियोजना के पहले और दूसरे प्रवेश द्वार को जोड़ते हुए कॉनकोर्स (सिटी सेंटर) भी बनाने का उद्देश्य है। काशी स्टेशन में रोज़ाना करीब 10 जोड़ी ट्रेनें रुकती हैं। इस कायाकल्प से स्टेशन की छवि पूरे तरीके से बदल जाएगी तथा इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने में ढाई साल का समय लग जाएगा।
- उन्होंने बताया कि इसके अलावा कैंट स्टेशन पर चार्ज़िंग सेंटर का टेंडर जारी होने से वाराणसी कैंट स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। यहाँ जनवरी से इलेक्ट्रिक ह्वीकल चार्ज़िंग फैसिलिटी पॉइंट बनना शुरू हो जाएगा। मार्च तक यहाँ इलेक्ट्रिक दोपहिया और ई-रिक्शा समेत सभी छोटे-बड़े वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मिलने लगेगी।
- ई-वाहनों को चार्ज करने के लिये फिलहाल वाराणसी में सरकारी या गैर-सरकारी स्तर पर कोई सुविधा नहीं है। मिर्ज़ामुराद में बना चार्ज़िंग स्टेशन सिर्फ ई-बसों के लिये ही है। ऐसे में कैंट स्टेशन पर बनने वाला ई-ह्वीकल चार्ज़िंग फैसिलिटी पॉइंट ऐसे वाहनों के लिये फायदेमंद साबित होगा।

## उत्तर प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में एचएमआईएस सेवा प्रारंभ

### चर्चा में क्यों ?

26 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में ई-सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) सुविधा शुरू की, जिससे मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होने वाले मरीजों को अब मोबाइल पर अपनी सेहत की कुंडली मिल सकेगी।

### प्रमुख बिंदु

- एचएमआईएस की शुरुआत एसएसपीजीआईसीएच नोएडा, स्वशासी मेडिकल कॉलेज एटा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, हरदोई, बस्ती, सिद्धार्थनगर, शाहजहाँपुर, अयोध्या, बहराइच, देवरिया, गाजीपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, बदायूँ, बांदा, जौनपुर, कन्नौज, जालौन एवं रिम्स सैफई में की गई है।
- उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि एचएमआईएस से, अगर मरीज के पास जाँच रिपोर्ट नहीं है तो भी ओपीडी में डॉक्टर ऑनलाइन रिपोर्ट देख सकेंगे। वह एक क्लिक पर संबंधित मरीज की पूरी केस हिस्ट्री जान सकेंगे। अब तक यह व्यवस्था एसजीपीजीआई, केजीएमयू, लोहिया संस्थान सहित 12 मेडिकल कॉलेजों में थी।

नोट :

- उन्होंने बताया कि एचएमआईएस को एंड्रायड फोन के प्लेस्टोर से डाउनलोड कर संबंधित अस्पताल में पंजीयन किया जा सकेगा। इस सॉफ्टवेयर से रोगियों को अस्पताल में किस दिन कौन-से डॉक्टर उपलब्ध होंगे, इसकी जानकारी मिल सकेगी।
- इस व्यवस्था से सभी मरीजों का पुख्ता डाटा तैयार हो सकेगा। इससे शोध करने, संसाधनों के विकास, व्यवस्था की निगरानी, भविष्य की योजना बनाने में आसानी होगी। एंबुलेंस, बेड एलॉटमेंट, भोजन आदि का रिकॉर्ड भी इस पर रहेगा। इससे कार्यों में पारदर्शिता लाई जा सकेगी।
- एचएमआईएस से मरीजों को ऑनलाइन पंजीयन, भुगतान, प्रिस्क्रिप्शन, लैब रिपोर्ट, फार्मेसी पर्ची, ओपीडी कार्ड, एडमिशन टिकट, डिस्चार्ज समरी मोबाइल पर मिल सकेगी। वह डॉक्टर की उपलब्धता, विशेष क्लीनिक का समय और ब्लड बैंक आदि की जानकारी आसानी से ले सकेंगे।
- सॉफ्टवेयर से रोगी का आधार, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट भी जोड़ा जाएगा। वहीं मरीजों को अस्पतालों में उपलब्ध दवाइयाँ आसानी से लिख सकेंगे तथा दवाओं की एक्सपायरी सूची भी देखी जा सकेगी।

## अब चौरीचौरा नाम से जाना जाएगा गोरखपुर का मुंडेरा बाज़ार नगर पंचायत

### चर्चा में क्यों ?

27 दिसंबर, 2022 को गोरखपुर के एसडीएम शिवम सिंह ने बताया कि गोरखपुर के मुंडेरा बाज़ार नगर पंचायत का नाम जल्द ही चौरीचौरा हो जाएगा। शासन के प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नाम परिवर्तन को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है।

### प्रमुख बिंदु

- एसडीएम शिवम सिंह ने बताया कि जंग-ए-आजादी के इतिहास में चौरीचौरा का नाम अमिट है। अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ चौरीचौरा में हुए प्रतिशोध के शताब्दी वर्ष के दौरान ही इस ऐतिहासिक स्थल से जुड़े तथ्यों को दुरुस्त करने का अभियान शुरू किया गया है।
- उन्होंने बताया कि तहसील और थाने का नाम तो पहले से ही चौरीचौरा है। पहले विधानसभा क्षेत्र का नाम मुंडेरा बाजार था। वर्ष 2012 के चुनाव से पहले इस विधानसभा क्षेत्र का नाम भी चौरीचौरा कर दिया गया। मुख्य बाजार मुंडेरा बाजार होने के कारण नगर पंचायत का नाम अभी तक मुंडेरा बाजार ही रह गया।
- गौरतलब है कि तत्कालीन डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर चौरीचौरा नगर पंचायत करने के लिये शासन को प्रस्ताव भेजा था। प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन ने गृह मंत्रालय को एनओसी के लिये प्रस्ताव भेज दिया था।
- एसडीएम शिवम सिंह ने बताया कि मुंडेरा बाजार एक बाजार है जो चौरीचौरा में समाहित है। पहले सिर्फ मुंडेरा बाजार के मतदाता थे और कुल 11 वार्ड थे। चुनाव से पूर्व विस्तारित क्षेत्र में भोपा बाजार, राघोपुर, चौरा, भगवानपुर, बाल बुजुर्ग गाँव भी सम्मिलित होने से अब 16 वार्ड और कुल मतदाताओं की संख्या 26 हज़ार हो गई है।

## पहली बार ईको टूरिज़्म थीम पर आयोजित होगा गोरखपुर महोत्सव

### चर्चा में क्यों ?

27 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के डीएफओ विकास यादव ने बताया कि प्रदेश में लोगों को जंगल और पर्यावरण की अहमियत समझाने के लिये वन विभाग पहली बार ईको टूरिज़्म की थीम पर गोरखपुर महोत्सव का आयोजन करेगा। यह महोत्सव 11 से 13 जनवरी, 2023 तक आयोजित किया जाएगा।

### प्रमुख बिंदु

- डीएफओ विकास यादव ने बताया कि जंगल मैराथन के तहत पाँच किलोमीटर तक बच्चों व सामाजिक संगठनों, सामान्य नागरिकों को जंगल के बीच घुमाया जाएगा। इस दौरान लोगों को जंगल और उसके माहौल के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह मैराथन देवरिया बाईपास के सूबा बाज़ार से शुरू होकर विनोद वन में खत्म होगा।

नोट :

- उन्होंने बताया कि गोरखपुर महोत्सव में मैराथन, फोटो प्रदर्शनी, सिनेमा और स्टाल के माध्यम से लोगों को वन की खासियत और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया व समझाया जाएगा। इसमें वन विभाग की कार्ययोजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।
- इसके अलावा ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित विश्व विख्यात पर्यावरणविद् माइक एच. पांडेय द्वारा निर्देशित पाँच अलग-अलग फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में फिल्म के माध्यम से लोगों को ईको टूरिज़्म की खासियत को समझाने की कोशिश की जाएगी।
- वन विभाग और बैंबू मिशन की ओर से तैयार बाँस के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर ईको टूरिज़्म फोटोग्राफी का भी स्टाल लगाया जाएगा। इसमें शहर के अलग-अलग सुंदर प्राकृतिक स्थलों की तस्वीरें होंगी।
- चिड़ियाघर में दो दिन कार्यक्रम होंगे। एक दिन नेचर वॉक होगा और दूसरे दिन चिड़ियाघर के वेटलैंड में बर्डवाच कार्यक्रम होगा। अभी तक पाँच स्कूलों के बच्चों को कार्यक्रमों से जोड़ा गया है।
- ज्ञातव्य है कि ईको टूरिज़्म का मतलब है- प्राकृतिक सौंदर्य के करीब जाना और उसका आनंद लेना। इसके तहत पर्यटकों को प्राकृतिक क्षेत्रों में ले जाया जाता है, ताकि के कुदरत के सौंदर्य का आनंद ले सकें। साथ ही पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूक हो सकें।

## टाइगर के बाद अब लेपर्ड कैट का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा दुधवा

### चर्चा में क्यों ?

28 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के दुधवा पार्क के निदेशक संजय पाठक ने बताया कि प्रदेश के दुधवा और दक्षिणी खीरी के जंगलों में पाए जाने वाले लेपर्ड कैट की पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गणना होगी और उनको विशेष संरक्षण दिया जाएगा।

### प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि दो महीने पहले दुधवा में हुई वर्कशॉप के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर लेपर्ड कैट के संरक्षण की दिशा में काम हो रहा है।
- विदित है कि दुधवा टाइगर रिज़र्व में बाघों को लेकर खास काम होता है। उनकी गणना, और संरक्षण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन दुधवा में पाए जाने वाले लेपर्ड कैट और उनकी प्रजाति की संख्या पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।
- जानकारों के मुताबिक दुधवा में बिग कैट, फिशिंग कैट और लेपर्ड केट समेत कई बिल्ली की प्रजाति पाई जाती है। लेपर्ड कैट और फिशिंग कैट सामान्य बिल्लियों से आकार में बड़ी होती हैं। उन पर तेंदुए जैसी धारियाँ या धब्बे भी नज़र आते हैं।
- दुधवा टाइगर रिज़र्व के निदेशक संजय पाठक ने बताया कि दुधवा में लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट आदि की काफी संख्या है। इनको अब तक देखकर ही दर्ज कर लिया जाता था, इनकी गणना का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था।

## साबरमती की तर्ज पर अयोध्या में बसेगी ग्रीनफील्ड टाउनशिप

### चर्चा में क्यों ?

29 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात के साबरमती की तर्ज पर अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप बसाने जा रही है। यह योजना 1438 एकड़ क्षेत्रफल में लाई जाएगी।

### प्रमुख बिंदु

- इस योजना के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष राज्य आवास विकास परिषद ने इसका प्रस्तुतीकरण किया। इस दौरान गुजरात के वास्तुविदों को भी बुलाया गया था। उन्होंने साबरमती ग्रीन फील्ड के बारे में जानकारी दी।
- इसके आधार पर आवास विकास परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप का आकार ऐसा तैयार किया जाए जो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो। इसके लिये ज़रूरत के आधार पर वास्तुविदों को भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर आवास विकास परिषद ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं।
- अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप की इस योजना को पहले चरण में 583 एकड़ क्षेत्रफल में बसाने की योजना है। पहले चरण के लिये 487 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जा चुका है।

नोट :

- दूसरे और तीसरे चरण में 855 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा टाउनशिप के आसपास व्यवसायिक क्षेत्र और पार्कों का इंतजाम किया जाएगा, जिससे लोगों को ज़रूरत के आधार पर सुविधाएँ मिल सके।
- विदित है कि वैदिक सिटी की परियोजना का मानक अहमदाबाद गिफ्ट सिटी के आधार पर तय होगा। नव्य अयोध्या परियोजना के अंतर्गत हाइवे के किनारे स्थित गाँवसभा शाहनवाजपुर एवं मांझा बरहटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड टाउनशिप योजना (वैदिक सिटी) में कई तरह के बदलाव भी किये जा रहे है और इसके लिये स्टैंडर्ड मानक भी निर्धारित किया जा रहा है।

## हिन्दी संस्थान के 46वें स्थापना दिवस पर 70 साहित्यकार सम्मानित

### चर्चा में क्यों ?

30 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का 46वाँ स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ। इसमें वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. राम कठिन सिंह, कथाकार डॉ. सुधाकर अदीब व संस्थान के निदेशक आरपी सिंह ने सभी श्रेणियों के कुल 70 साहित्यकारों को सम्मानित किया।

### प्रमुख बिंदु

- 26 वर्षों के अनवरत् लेखन से रचित महाकाव्य विधा की पुस्तक 'अथर्वा, मैं वही वन हूँ' के लिये भोपाल के आनंद कुमार सिंह को 'तुलसी पुरस्कार' दिया गया। कविता संग्रह 'राम धरा पर पुन: पधारो' के लिये शंकर सिंह को श्रीधर पाठक पुरस्कार से नवाजा गया। नाटक विधा की रचना 'कालपुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर' के लिए गाजियाबाद के साहित्यकार जयवर्धन जेपी को भारतेंदु हरिश्चन्द नामित पुरस्कार मिला।।
- यात्रा वृत्तांत विधा में पुस्तक 'सपनों का शहर सैन फ्रांसिस्को' के लिए नोएडा की साहित्यकार जयश्री पुरवार को अज्ञेय नामित पुरस्कार मिला। उपन्यास विधा में 'कंथा' पुस्तक के लिये वाराणसी के साहित्यकार श्याम बिहारी श्यामल को प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया।
- बाल साहित्य विधा की पुस्तक 'मां कह एक कहानी' के लिये गाज़ियाबाद की साहित्यकार श्रद्धा पांडेय को सूर पुरस्कार से नवाजा गया। इतिहास विधा की पुस्तक 'सियासत का सबक' के लेखक यूपी के पूर्व डीजीपी और भाजपा सांसद बृजलाल को आचार्य नरेंद्र देव पुरस्कार मिला।
- पत्रकारिता विधा की पुस्तक 'क्रोनोलॉजी इन कोविडटून्स' के लिये लखनऊ के पत्रकार हरिमोहन वाजपेयी 'माधव' को धर्मवीर भारती सर्जना पुरस्कार से नवाजा गया। कहानी संग्रह विधा की पुस्तक 'अनुभव के बोल' के लिये लखनऊ के रामजी भाई को यशपाल पुरस्कार मिला। इसमें 51 कहानियों का संग्रह है।

## GIS 2023: यूपीसीडा ने हासिल किये एक लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 83 हज़ार करोड़ रुपए के एमओयू साइन

### चर्चा में क्यों ?

30 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रेदश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया कि यूपीसीडा ने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव निवेशकों से हासिल किये हैं। इनमें से 83 हज़ार करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर भी किये जा चुके हैं।

### प्रमुख बिंदु

- यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया कि इन एमओयू को 10-12 फरवरी, 2023 को लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा।
- सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया कि राज्य सरकार उत्तर प्रेदश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है। लक्ष्य प्राप्ति के लिये यूपीसीडा के वरिष्ठ अधिकारियों की नौ टीमों का गठन कर पहले चरण में 22 ज़िलों में निवेशकों व उद्यमियों के साथ बैठकें की गईं। इस दौरान निवेशकों के साथ एमओयू किया गया।
- इनमें मुख्यरूप से फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क, वेयरहाउसिंग, पेपर उद्योग, मेडिकल क्षेत्र, बायोफ्यूल, खिलौना उत्पाद, डाटा सेंटर, आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में निवेश की रुचि दिखाई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पूर्व टीम गठित कर अन्य ज़िलों में भी निवेश गोष्ठियाँ की जाएंगी।

नोट :

- यूपीसीडा ने जो एमओयू किये हैं, उनसे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो प्रमुख एमओयू हुए हैं, उनमें गाज़ियाबाद में ग्रपेकर्स नेटवर्क द्वारा 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर 10000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। गौतमबुद्धनगर में मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउस पार्क की स्थापना पर 8 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इससे 1000 लोगों को नौकरी मिलेगी। कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट (यूपी) लिमिटेड 6000 करोड़ रुपए के निवेश से लेदर उद्योग स्थापित करेगा। इससे दो लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
- प्रतापगढ़ में धरित्री सॉल्यूशन, एसएमआरएम इनोवेटिव वेंचर्स प्रा. लि. द्वारा 9000 करोड़ के निवेश से इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने से 50 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है। सोनभद्र में सिटी गोल्ड इंडस्ट्रियल लि. द्वारा 3000 करोड़ के निवेश से सीमेंट प्लांट के माध्यम से एक हज़ार लोगों को रोज़गार देगी तो लखनऊ में वेलस्पन व लॉजिस्टिक्स पार्क्स प्रा. लि. द्वारा 2000 करोड़ रुपए के निवेश से बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- हाई फ्लो इंडस्ट्रीज द्वारा आगरा और अयोध्या में 3-3 हज़ार, गाजियाबाद में 14 हज़ार करोड़, गोरखपुर में 1200 करोड़, कानपुर में 7500 करोड़, लखनऊ में 3500 करोड़, अलीगढ़ में 300 करोड़, प्रयागराज में 35000 करोड़, सूरजपुर में 9000 करोड़, वाराणसी में 2000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही सभी ज़िलों में 5 लाख से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
- निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराने के लिये यूपीसीडा ने 15 हज़ार एकड़ से अधिक का लैंड बैंक तैयार किया है। लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउस स्थापना के लिये वाराणसी में इंडियन कॉर्पोरेशन ने 2000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित किया है।
- विभिन्न क्षेत्रों में और भी कई निवेश हुए हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 23000 करोड़ से अधिक, निजी औद्योगिक पार्क क्षेत्र में 21 हज़ार करोड़, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग में लगभग 10000 करोड़, चमड़ा और जूता उद्योग में 6000 करोड़, गैर-धात्विक और खनिज उत्पाद क्षेत्र में लगभग 4000 करोड़ और जैव ईंधन क्षेत्र में लगभग 850 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है।
- प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिये होने वाले निवेश के लक्ष्य को 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 17 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इसके लिये सभी विभागों के पुराने निवेश लक्ष्यों को भी संशोधित किया गया है। यूपीसीडा का निवेश लक्ष्य भी 70 हज़ार करोड़ रुपए से बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपए कर दिया है। यूपीसीडा ने लक्ष्य संशोधित किये जाने से पहले ही 80 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर लिये हैं।

The Vision

नोट :